श्री अनन्त गंगाराम गीते: सर, पावर जनरेशन में तो आज हम निजी क्षेत्र में हैं। कई प्रोजेक्ट्स हैं जो अलग-अलग राज्यों में निजी क्षेत्र के लगे हुए हैं और भविष्य में भी यदि कोई निजी क्षेत्र पावर जनरेशन में आगे आना चाहते है तो उसके लिए सरकार की ओर से पूरी सहायता की जाएगी।

श्री जयन्ती लाल बरोट: सभापति जी, मैं यह जानना...

श्री सभापति: बस हो गया, बैठिए।

मंत्री महोदय, आप जानते हैं कि बिजली में ट्रांसमिशन लासिज 24,000 करोड़ रुपए के हैं। इनको रोकने का यदि प्रयत्न किया जाए तो इस बिजली की समस्या का बहुत हद तक समाधान हो सकता है।

श्री अनन्त गंगाराम गीते: सभापति जी, मैं आपके मत से सहमत हूं। लगभग 30,000 करोड़ रुपए का घाटा है और इसको बचाने के लिए प्रयास केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की ओर से अलग-अलग योजनाओं के तहत किए जा रहे हैं और निश्चित रूप से इससे हमें राहत मिल सकती है।

कोकिंग कोयले का उत्पादन

***308. श्री कपिल सिब्बल:††**
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में कोकिंग कोयले का उत्पादन गत वर्षों से लगातार कम होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 के दौरान यह उत्पादन कितना था;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त कोयले के उत्पादन की मात्रा के संबंध में क्या आकलन है; और

(घ) उत्पादन में निरंतर कमी आने के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुंडा): (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर रख दिया गया है।

---

††सभा में यह प्रश्न श्री कपिल सिब्बल द्वारा पूछा गया।

विवरण

(क) जी हां, पिछले कुछ वर्षों से कोकिंग कोयले का उत्पादन घटता रहा है। तथापि, इस वर्ष (2002-2003) कोकिंग कोयले के उत्पादन में पिछले वर्ष की उपलब्धि की तुलना में थोड़ी वृद्धि होने की संभावना है।

(ख) देश में 1999-2000 के दौरान कोकिंग कोयले का उत्पादन 32.98 मिलियन टन था।

(ग) चालू वर्ष में 2002-03 के लिए आंकलित कोकिंग कोयला उत्पादन अनंतिम रूप से 29.99 मिलियन टन आंका गया है।

(घ) कोकिंग कोयले के उत्पादन में कमी होने के प्रमुख कारण हैं-(i) क्षीयमान अच्छी क्वालिटी के कोकिंग कोयला भंडारों का प्रयोग धुलाई के पश्चात् अधिकांशत: इस्पात संयंत्रों द्वारा किया जाता है। (ii) भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास की बाधाओं से चालू खान में उत्पादन में अवरोध पैदा होता है और बी॰सी॰सी॰एल॰ तथा सी॰सी॰एस॰ में नई परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भी विलम्ब होता है जो सी॰आई॰एल॰ की, कोकिंग कोयले का उत्पादन करने वाली, प्रमुख सहायक कंपनियां हैं। बी॰सी॰सी॰एल॰ की रुग्णता भी एक महत्वपूर्ण कारण है।

Production of coking coal

†*308. SHRI KAPIL SIBAL:††
SHRI RAJIV RANJAN SINGH 'LALAN':

Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that production of coking coal in the country is decreasing constantly since last year;

(b) if so, the production during the year 1999-2000;

(c) the assessment with regard to the production of said coal during the current financial year; and

(d) the reasons for decreasing production constantly?

THE MINISTER OF COAL (SHRI KARIYA MUNDA): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

---

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Kapil Sibal.

Statement

(a) Yes, Sir. Production of coking coal has been decreasing during the past few years. However, coking coal production in this year (2002-2003) is likely to increase marginally over last year's achievement.

(b) Production of coking coal during 1999-2000 was 32.98 million tonnes in the country.

(c) Assessed coking coal production for the current financial year 2002-2003 is provisionally estimated at 28.99 million tonnes.

(d) Principal reasons for decrease in production of coking coal (i) dwindling of good quality coking coal reserves mostly utilized in steel plants after washing (ii) constraints of land acquisition and rehabilitation resulting in restriction of production in ongoing mines and also delay in implementation of new projects in BCCL and CCL which are the major coking coal producing subsidiaries of CIL. Sickness of BCCL is also an important reason.

SHRI KAPIL SIBAL: Mr. Chairman, Sir, with the answer, there is one fact that I would like to place on record, that the production of coking coal in 1997-98 was 45 million tonnes, in 1999-2000 it was 32 million tonnes and the projected production for 2002-03 is 27 million tonnes. So, there is a constant decline, and on the other hand, the imports, especially from Australia, are increasing and the reason for decline is that the new projects are not moving fast enough because BCCL is a sick company and no new projects are being now put forward. And the second reason is, that the ash content of our coal has risen up to 30 per cent whereas the requirement is 17 per cent, especially for steel units.

The first question I have to the Minister is this: How many new projects are there; for how long they have been pending and how quickly do they intend to complete them?

श्री कड़िया मुंडा: सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने कहा है कि वह बात सही है क्योंकि कुकिंग कोल हमारे दो क्षेत्रों में अधिक पैदा होता है - एक, बी॰सी॰सी॰एल॰ और दूसरा, सी.सी. एंफ.एल. । बी.सी.सी.एल. बहुत पुरानी कंम्पनी है और वहां पर जितनी भी खान हैं वे करीब-करीब रुग्ण हो चुकी हैं और इस दृष्टिकोण से जो कुकिंग कोल का उत्पादन होना चाहिए उसमें कमी हो

रही है। इस दृष्टिकोण से यह कोशिश की जा रही है कि हम कुछ नई योजनाओं को लें। परन्तु नई योजनाओं को लेने में एक दिक्कत आ रही है जो वहां भूमि अधिग्रहण और विस्थापन की समस्या है इसमें राज्य सरकार को जिस तरह से सहयोग करना चाहिए वह नहीं कर पा रहे हैं। इससे नई योजनाओं को चलाने के लिए जो हमारे लिए जरूरी चीजें हैं पूरी नहीं हो पा रही हैं जिससे जो और अधिक कुकिंग कोल का उत्पादन होना चाहिए परन्तु उसमें अभी हम उतने सक्षम नहीं रहे हैं।

श्री सभापति: अच्छा होगा आप इस संबंध में राज्य सरकारों से मिलकर बैठ कर बातें करें, समस्या का समाधान हो जाएगा।

श्री कड़िया मुंडा: प्रयास जारी है।

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, he has not answered my question. I asked him. How many projects are there; for how long they have been pending and when they intend to complete them? He has not answered any of these questions. Please tell us. Or has the Government of India decided to throw up its hands and say, 'no we cannot do anything about it'? That also you can tell us. It is not a problem. Please tell us.

श्री सभापति: बोलिए, क्या आपके पास संख्या है? वह जो पूछ रहे हैं इसके बारे में क्या जानकारी है?

श्री कड़िया मुंडा: मैं उनको बाद में भेज दूंगा।

SHRI KAPIL SIBAL: This is no way. (*Interruptions*)

श्री सभापति: आपका क्वेश्चन देख कर कम से कम आपको एक तसल्ली तो दी है कि वह जवाब बाद में भेज देंगे।

श्री कपिल सिब्बल: सर, यह गलत बात है, यह ठीक नहीं है, सर।

श्री सभापति: आप दूसरा कर लीजिए जिसका वे जवाब देंगे।

श्री कपिल सिब्बल: ठीक है सर, मैं सप्लीमैंट्री करता हूं।....(**व्यवधान**) मैंने तो सप्लीमैंट्री भी नहीं किया, आप दूसरे को कह रहे हैं।

श्री सभापति: करिए न, मैं यही तो कह रहा हूं।

श्री कपिल सिब्बल: जो हमारा ऐश-कंटेंट है कोल का वह 30 प्रतिशत है और स्टील माइंस को 17 प्रतिशत चाहिए। तो मंत्री जी यह बताएंगे कि कितनी वाशरीज हैं?...(**व्यवधान**) सर, फिर नहीं बताएंगे।

सभापति: अच्छा बोलिए।

श्री कपिल सिब्बल: सर, मैं यह गुजारिश करुंगा कि जब अगली बार मंत्री जी यहां आएं तो पूरी तैयारी करके आएं।

श्री सभापति: यह ठीक रहेगा। श्री राजीव रंजन सिंह ''ललन''।

अब आप क्या करेंगे, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': सर, पूछने तो दीजिए।

'हरियाली' योजना के अन्तर्गत सूखा प्रभावित राज्यों को प्राथमिकता

***309. प्रो॰ अलका क्षत्रिय:††**

श्री बालकवि बैरागी:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्षा जल के संग्रहण, संरक्षण और सिंचाई से जुड़ी 1070 करोड़ रुपये की प्रधान मंत्री द्वारा वित्त पोषत नई ''हरियाली'' योजना देश की दो लाख बत्तीस हजार पंचायतों को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो दो लाख बत्तीस हजार पंचायतों में से कौन-कौन से राज्य हैं जो इस नई ''हरियाली'' योजना से लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत सूखा-प्रभावित राज्यों को प्राथमिकता दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शान्ता कुमार): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(क) से (घ) नए कार्यक्रम 'हरियाली' में ग्रामीण विकास मंत्रालय के वाटरशेड विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत भावी परियोजनाओं का कार्यान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के जरिए किए जाने की परिकल्पना की गई है।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अन्तर्गत शामिल करने हेतु देश के सूखा प्रवण तथा मरुभूमि क्षेत्रों को पहले ही अभिज्ञात किया जा चुका है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अन्तर्गत 16 राज्यों के 182 जिलों में 972 ब्लॉकों को तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अन्तर्गत 7 राज्यों के 40 जिलों में 227

---

††सभा में यह प्रश्न प्रो. अलका क्षत्रिय द्वारा पूछा गया।